आज का मौसम
अधिकतम 38° C
न्यूनतम 30° C
सूर्य अस्त (आज) 7:20
सूर्य उदय (कल) 5:33

दैनिक समाचार पत्र
जीत सच्ची खबर की
जीत समाचार
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश

वर्ष : 13 अंक : 300 मूल्य : 2 रू पृष्ठ : 8
शनिवार
18 जुलाई 2026
RNI NO : PUNHIN/2013/60106 www.zeetsamachar.com

अनमोल वचन

"जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से गंदा नहीं होता उसी तरह आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से विचलित या माया से अशुद्ध नहीं होता।"

प्रधानमंत्री मोदी का हाथ से लिखा 'वंदे मातरम' पोस्टकार्ड जाएगा अंतरिक्ष, 18 जुलाई को होगी विक्रम-1 की ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली/श्रीहरिकोटा। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस अपने पहले ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 की टेस्ट फ्लाइट-1 लॉन्च करेगा। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा 'वंदे मातरम' पोस्टकार्ड भी अंतरिक्ष की यात्रा करेगा।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मिशन के विशेष पेलोड में प्रधानमंत्री का हस्तलिखित संदेश शामिल किया गया है। इसके अलावा स्काईरूट की टीम, निवेशकों, नीति-निर्माताओं और दुनिया भर के शुभचिंतकों के हाथ से लिखे संदेश भी इस मिशन के साथ भेजे जाएंगे।

स्काईरूट एयरोस्पेस ने बताया कि ये सभी यादगार संदेश 'मिशन आगमन' अभियान का हिस्सा हैं, जो भारत के उभरते निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम के प्रति सामूहिक समर्थन और विश्वास का प्रतीक है।

विक्रम-1 मिशन में कॉस्मोसर्व, डी-क्यूब्ड और स्काईरूट के स्कोप के टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पेलोड भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कॉसमहस डायमंड्स द्वारा तैयार किया गया 'कॉस्मिक ब्लूम' आर्टवर्क और एक माइक्रो-आर्ट पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

यह लॉन्च 18 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किया जाएगा। यह भारतीय धरती से किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट की पहली उड़ान का प्रयास होगा, जिसे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।

कंपनी के अनुसार लॉन्च के लिए आवश्यक एयरस्पेस और समुद्री मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं तथा रहकेट के उड़ान मार्ग और संभावित प्रभाव क्षेत्र के लिए आवश्यक सुरक्षा नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।

मुख्य बातें:

- 18 जुलाई को होगी विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1।
- पीएम मोदी का हस्तलिखित 'वंदे मातरम' पोस्टकार्ड जाएगा अंतरिक्ष।
- भारत के पहले निजी ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट की उड़ान का प्रयास।
- मिशन में कई तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और विशेष आर्ट पेलोड भी शामिल।

संक्षिप्त न्यूज

पुरी में आस्था का सैलाब: रथ यात्रा के दूसरे दिन 12 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, भक्त बोले 'शब्दों में बयां नहीं हो सकता यह अनुभव'

पुरी/ओडिशा(एजेंसी)। भगवान श्रीजगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को पुरी पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। महाप्रभु के दर्शन और रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश-विदेश से आए करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने पुरी पहुंचकर आस्था का परिचय दिया। दूसरे दिन भगवान जगन्नाथ के रथ पर विधि-विधान से आरती और दर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

रथ यात्रा में पहली बार शामिल हुए कई श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार और आध्यात्मिक अनुभव बताया। एक भक्त ने कहा कि पहली बार रथ यात्रा में शामिल होकर उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ और यहां बिताया हर पल उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा।

एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से उन्हें इस पावन पर्व का हिस्सा बनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस दिव्य अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

एक भक्त ने भावुक होकर कहा कि "इससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता कि स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को भगवान के मंदिर से बाहर आने का दिव्य दृश्य देखकर ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड प्रभु के स्वागत में उमड़ पड़ा हो। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौरान हुई बारिश मानो स्वर्ग का आशीर्वाद प्रतीत हो रही थी।

पहली बार पुरी पहुंचे एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि भगवान जगन्नाथ बिना किसी भेदभाव के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रभु के दर्शन करते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।

भगवान जगन्नाथ की यह भव्य रथ यात्रा देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का अनुपम संगम बनी हुई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यह पावन आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

वन संरक्षण में जनभागीदारी सबसे बड़ी ताकत- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी केवल वनों के प्रशासक नहीं, बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहर के संरक्षक भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनभागीदारी से वन संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावी, मजबूत और दीर्घकालिक बनेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का दायित्व केवल देश की पर्यावरणीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सतत विकास के वैश्विक प्रयासों में भी अहम योगदान देंगे।

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को वन क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वनों और आसपास रहने वाले लोगों की वैध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे समाधान विकसित किए जाने चाहिए, जिनसे प्रकृति और स्थानीय समुदाय दोनों को समान लाभ मिले।

राष्ट्रपति मुर्मु ने संरक्षण, वन-पुनर्स्थापन और सतत आजीविका से जुड़ी योजनाओं में जनजातीय समुदायों, वनवासियों, महिलाओं, किसानों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों के अनुभव और सुझाव संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है और भारतीय वन सेवा के युवा अधिकारी देश की विकास यात्रा को हरित, समावेशी और सतत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में भारतीय वन सेवा के 2024 और 2025 बैच के कुल 242 प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें 2024 बैच के 111 तथा 2025 बैच के 131 अधिकारी शामिल हैं। दोनों बैचों में भूटान के दो-दो प्रशिक्षु अधिकारी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर सफर कर उत्साहित हुए छात्र, बोले - 'भारत की पहली प्रदूषणमुक्त ट्रेन का हिस्सा बनना गर्व की बात'

जींद/हरियाणा (एजेंसी)। भारत के रेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फूलों और गुब्बारों से सजी यह अत्याधुनिक ट्रेन अब जींदसोनीपत रेलखंड पर नियमित रूप से संचालित होगी।

उद्घाटन यात्रा में शामिल छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। एक छात्र ने कहा, "यह भारत की पहली प्रदूषणमुक्त हाइड्रोजन ट्रेन है। इसमें सफर करना हमारे लिए गर्व और ऐतिहासिक अनुभव है। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश का बड़ा कदम है और हमें खुशी है कि हम इसके पहले यात्रियों में शामिल हैं।"

कार्यक्रम में मौजूद एक शिक्षक ने कहा कि बच्चों के लिए इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक को करीब से देखने और समझने का अवसर छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

ट्रेन मैनेजर नितिन पारिख ने बताया कि यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन-चालित यात्री ट्रेनों में से एक है। उन्होंने कहा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली इस ट्रेन से केवल जल वाष्प निकलती है, जिससे किसी प्रकार का कार्बन प्रदूषण नहीं होता। इससे पहले इलेक्ट्रिक, डीजल और सीएनजी ट्रेनों के सफल संचालन के बाद अब भारत ने हाइड्रोजन तकनीक में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से भारत में डिजाइन, इंजीनियर और विकसित की गई है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां हाइड्रोजन-चालित यात्री ट्रेनें परिचालन में हैं।

जीत सच्ची खबर की
जीत समाचार
www.zeetsamachar.com

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्रिनगर में 14 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में 14 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान नेताजी सुभाष प्लेस क्षेत्र में पांच सड़कों और एक नाले के पुनर्निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, जबकि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई आठ प्रमुख सड़कों का भी लोकार्पण किया गया।

इन परियोजनाओं के तहत 6.25 करोड़ रुपये की लागत से विकसित लॉरेंस रोड, महर्षि परशुराम मार्ग, परवाना रोड, जी एवं एच शकूरपुर रोड, एकलव्य मार्ग, तिरुवल्लुवर मार्ग, वीर हेमू मार्ग सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जनता को समर्पित किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, नालों, कॉलोनियों और झुग्गी-बस्तियों के विकास के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि त्रिनगर विधानसभा लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझती रही, लेकिन अब क्षेत्र में व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जल निकासी की समस्या में राहत मिलेगी और स्थानीय लोगों को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी के प्रत्येक क्षेत्र में समान और तेज विकास सुनिश्चित करना है।

शुक्रवार को विश्वभर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, न्याय और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।17 जुलाई को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य न्याय की स्थापना को बढ़ावा देना, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना तथा विश्व शांति, सुरक्षा और मानवता के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर लोगों को एकजुट करना है।

यह दिवस 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाए जाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसी संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका उद्देश्य नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना है।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस दुनिया को यह संदेश देता है कि न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा और कानून का सम्मान किसी भी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण समाज की मजबूत नींव हैं। यह दिवस वैश्विक समुदाय को न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, निष्पक्ष तथा सुलभ बनाने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026: पहली बार विजेता टीम को मिलेगी चौंपियनशिप रिंग, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होगा महामुकाबला

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और दुनिया भर के फुटबहल प्रेमियों की निगाहें अब फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं। इस बार टूर्नामेंट सिर्फ रोमांचक मुकाबले के लिए ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पहल के लिए भी याद रखा जाएगा। फीफा ने पहली बार विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ 'चौंपियनशिप रिंग' देने की घोषणा की है।

फीफा के अनुसार, यह चौंपियनशिप रिंग अमेरिकी खेलों की लोकप्रिय परंपरा से प्रेरित है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि की एक स्थायी और विशेष यादगार देना है। रिंग के एक ओर फीफा वर्ल्ड कप ट्रहफी की आकृति होगी, जबकि दूसरी ओर विजेता टीम के अनुरूप विशेष डिजाइन तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिंग पर अलग क्रमांक होगा और उसके साथ प्रामाणिकता का आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

फाइनल मुकाबले के तुरंत बाद विजेता टीम के कप्तान और मुख्य कोच को प्रतीकात्मक रूप से रिंग प्रदान की जाएगी। इसके बाद खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए 30 विशेष कस्टमाइज्ड रिंग तैयार कर आधिकारिक रूप से सौंपी जाएंगी।

फीफा ने बताया कि इस चौंपियनशिप रिंग का कुल 2,026 पीस का लिमिटेड एडिशन बनाया जाएगा। इनमें से 30 रिंग विश्व चौंपियन टीम को दी जाएंगी, जबकि शेष 1,996 रिंग आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त स्मृति-चिह के रूप में दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

इस बार विश्व कप का खिताबी मुकाबला यूरोपीय चौंपियन स्पेन और मौजूदा विश्व चौंपियन अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2–1 से हराकर लगातार दूसरी बार और कुल सातवीं बार फाइनल में प्रवेश किया है।

अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पूरे टूर्नामेंट में शानदार लय में रहे हैं। उन्होंने अब तक आठ गोल किए हैं और विश्व कप करियर में उनके कुल गोलों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। ऐसे में फाइनल में भी टीम को अपने कप्तान से एक और यादगार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

फुटबॉल इतिहास में पहली बार चौंपियनशिप रिंग की शुरुआत विश्व कप को और अधिक यादगार बनाने के साथ-साथ विजेता खिलाड़ियों के लिए सम्मान का एक नया प्रतीक बनेगी।

अमेरिका के 250वें स्वतंत्रा दिवस समारोह में चमका भारत का गौरव, आईएनएस सुदर्शनी ने दिखाई समुद्री शक्ति

संवाद न्यूज एजेंसी

वाशिंगटन। भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत आयोजित सेल 250 और इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 में सफलतापूर्वक भाग लेकर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और नौसैनिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक भागीदारी को भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि आईएनएस सुदर्शनी ने नॉरफॉक, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क और बोस्टन सहित अमेरिका के चार प्रमुख बंदरगाहों का दौरा किया। दूतावास ने इसे भारत की समुद्री परंपरा और दोनों देशों के बढ़ते रक्षा एवं समुद्री सहयोग का प्रतीक बताया।

आईएनएस सुदर्शनी की यह लंबी यात्रा अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समुद्री समारोह का हिस्सा रही। इस अवसर पर जहाज ने भारत की नौसैनिक परंपराओं, पेशेवर क्षमता और वैश्विक समुद्री सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया।

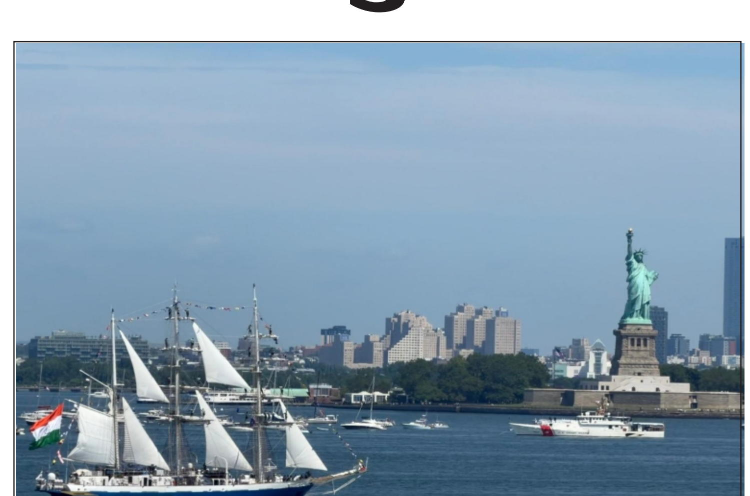

बोस्टन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय महावाणिज्य दूत रघुराम एस. ने कहा कि आईएनएस सुदर्शनी एशिया और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र का एकमात्र पारंपरिक सेल ट्रेनिंग शिप है, जिसने इस प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेने के लिए लगभग साढ़े पांच महीने की समुद्री यात्रा पूरी कर अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच बनाई।

इस दौरान जहाज पर आयोजित विशेष स्वागत समारोह और मीडिया ब्रीफिंग में भारत-अमेरिका समुद्री सहयोग, नौसैनिक संबंधों और साझा रणनीतिक हितों पर भी चर्चा हुई।

वहीं, भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय रक्षा विंग ने यूएस आर्मी वहर कहलेज के प्रतिनिधिमंडल के साथ सैन्य रणनीति और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

आईएनएस सुदर्शनी की यह ऐतिहासिक यात्रा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग का सशक्त प्रतीक मानी जा रही है।

देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरियाणा को 14,700 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात

जीत समाचार ब्यूरों

रोहतक/जींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। यह पहल हरित ऊर्जा, आधुनिक परिवहन और विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

इस अवसर का सीधा प्रसारण महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के टैगोर अहडिटोरियम में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

अपने संबोधन में उषा प्रियदर्शी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में भारत की बड़ी छलांग है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति राज्य महिला आयोग की प्रतिबद्धता दोहराते हुए महिलाओं से बिना किसी भय के अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

उषा प्रियदर्शी ने समाज से महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाने का आह्वान करते हुए कहा, सशक्त महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थी कमलेश पत्नी अशोक कुमार तथा कमलेश पत्नी सुरेश (गांव काहनौर) को नए आवासों की चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश कराया गया।

इस अवसर पर पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, भाजपा जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका, मेयर रामअवतार वाल्मीकि, जिला परिषद चेयरपर्सन मंजू हुड्डा, प्रदेश सचिव रेणु डाबला, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल, भाजपा नेता दीपक निवास हुड्डा, उपायुक्त सचिन गुप्ता, पुलिस एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित कालका रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित, हरियाणा को मिली नई सौगात

जीत समाचार ब्यूरों

कालका (हरियाणा)। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित कालका रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।

पुनर्विकसित कालका रेलवे स्टेशन को आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर प्रतीक्षालय, उन्नत बुनियादी ढांचे, सुगम आवागमन और मजबूत कनेक्टिविटी के साथ विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा।

कालका रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में स्टेशन के आधुनिकीकरण से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। पुनर्विकसित कालका रेलवे स्टेशन इसी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आधुनिक भारत के विकसित रेलवे नेटवर्क की झलक प्रस्तुत करता है।

इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त किया और इसे हरियाणा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों के प्रति किया जागरूक, रोहतक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

जीत समाचार ब्यूरों

रोहतक। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन तथा डीएलएसए की सचिव डॉ. तरन्नुम खान के निर्देशानुसार शमशेर बहादुर सक्सेना कहलेज अहफ लह, रोहतक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसे समय पर, समान और निष्पक्ष कानूनी सहायता उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी को निरूशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक से संपर्क कर सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के सभी विधि महाविद्यालयों में लीगल एड क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी और आम नागरिक अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से इन सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने और समाज में विधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। डॉ. खान ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ और हरित पर्यावरण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही समाधान समारोह, राष्ट्रीय लोक अदालत, टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों से आग्रह किया गया कि वे जरूरतमंद लोगों तक निरूशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचाकर समाज में न्याय और विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर –
'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'

पंजाब में कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क -राज्य के सामने बड़ी चुनौती

पंजाब लंबे समय से कानून-व्यवस्था और संगठित अपराध की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में गैंगस्टर नेटवर्क, नशा तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई, फिरौती, लक्षित हत्याओं और सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लगातार इन नेटवर्कों पर कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बदलते तौर-तरीकों के कारण यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है।

पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसका फायदा उठाकर कई बार ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ, हथियार और गोला-बारूद भेजने के प्रयास किए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियां नियमित रूप से ऐसे ड्रोन को पकड़ने और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान चलाती हैं। इन गतिविधियों का सीधा संबंध कई बार संगठित अपराध और गैंगस्टर गिरोहों से भी जोड़ा जाता है।

गैंगस्टर नेटवर्क अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कई मामलों में विदेशों में बैठे अपराधी सोशल मीडिया, इंटरनेट कॉलिंग और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए अपने नेटवर्क का संचालन करते हैं। वे रंगदारी वसूलने, धमकी देने और आपराधिक घटनाओं की साजिश रचने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं। इससे पुलिस के सामने जांच और अपराध नियंत्रण की चुनौती और बढ़ जाती है।

राज्य में समय-समय पर गैंगवार, फिरौती, कारोबारियों को धमकियां, अवैध हथियारों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारियों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं से आम जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती है और व्यापारिक माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार और पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है।

पंजाब पुलिस ने हाल के वर्षों में कई बड़े अभियान चलाकर गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने का दावा किया है। विशेष ऑपरेशन सेल, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स , साइबर विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों के सहयोग से अनेक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अवैध हथियारों की बरामदगी, बैंक खातों की जांच, संपत्तियों पर कार्रवाई और वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं।

नशा तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच संबंध भी चिंता का विषय है। जांच एजेंसियों का मानना है कि कई आपराधिक गिरोह नशे के कारोबार से आर्थिक लाभ प्राप्त कर अपने नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। इसलिए नशे के खिलाफ अभियान और गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए युवाओं को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल सुविधाएं, कौशल विकास और नशामुक्ति कार्यक्रमों से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासन को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिससे युवा अपराध और नशे से दूर रहें।

इसके अलावा आधुनिक तकनीक का उपयोग, बेहतर खुफिया तंत्र, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, राज्यों के बीच समन्वय और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाकर संगठित अपराध पर अधिक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

निष्कर्ष : कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क पंजाब के सामने एक गंभीर चुनौती हैं, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय और समाज के सहयोग से इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में प्रयास जारी हैं। दीर्घकालिक सफलता के लिए अपराध नियंत्रण के साथ-साथ युवाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

कमल पवार (सम्पादक)

दैनिक समाचार पत्र
जीत समाचार
जीत सच्ची ख़बर की

मुद्रक, प्रकाशक व सम्पादक : कमल पवार द्वारा 11368, पवित्र नगर, वालिया कालोनी हैबोवाल कलां, लुधियाना से प्रकाशित एंव जीत लुधियाना प्रिंटर्स हैबोवाल लुधियाना से मुद्रित।

सम्पादक : कमल पवार इस अंक मे प्रकाशित एंव समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा उत्पन्न समस्त विवाद लुधियाना न्यायालय के अधीन होगे।

R.N.I NO. PUN/HIN/2013/60106

Contact us :- +91-98030-25111.

आज की प्रमुख हस्ती

बच्चों में मोबाइल का बढ़ता दुरुपयोग: ज्ञान से अधिक मनोरंजन की ओर बढ़ते कदम

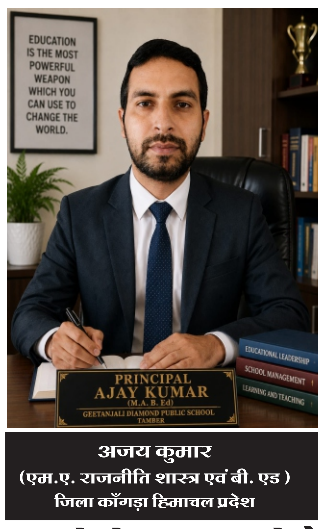

अजय कुमार
(एम.ए. राजनीति शास्त्र एवं बी. एड)
जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश

आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है। मोबाइल फोन ने शिक्षा, संचार और जानकारी प्राप्त करने के अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं। यदि इसका सही उपयोग किया जाए, तो यह बच्चों के लिए ज्ञान का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। कोरोना महामारी के दौरान अहनलाइन कक्षाओं और घर से पढ़ाई की आवश्यकता के कारण बच्चों के हाथों में मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण बड़ी संख्या में पहुँचे। उस समय यह शिक्षा का आवश्यक साधन था, लेकिन महामारी समाप्त होने के बाद भी अनेक बच्चों में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग की आदत बनी रही।

आज अधिकांश बच्चे मोबाइल का उपयोग पढ़ाई और सीखने की अपेक्षा मनोरंजन, ऑनलाइन गेम, शॉर्ट वीडियो और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने के लिए कर रहे हैं। यह स्थिति अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के लिए चिंता का विषय बन चुकी है।मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों की समस्या, नींद में कमी, एकाग्रता में गिरावट और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। कई बच्चे परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने के बजाय आभासी दुनिया में अधिक व्यस्त रहने लगे हैं। इससे उनके व्यवहार, अध्ययन और व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विडंबना यह है कि जिस मोबाइल में विश्वभर का ज्ञान उपलब्ध है, उसका उपयोग बहुत कम बच्चे सीखने के लिए करते हैं। यदि प्रतिदिन कुछ समय शैक्षिक वीडियो, ई-पुस्तकों, विज्ञान, भाषा, सामान्य ज्ञान और नई तकनीकों को सीखने में लगाया जाए, तो मोबाइल एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सकता है। दुर्भाग्य से अधिकांश समय मनोरंजन में ही व्यतीत हो जाता है।

इस समस्या का समाधान केवल बच्चों से अपेक्षा करने से नहीं होगा। अभिभावकों और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की उचित सीमा तय करनी चाहिए, पढ़ाई, खेल-कूद और पारिवारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए तथा उन्हें मोबाइल का सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग सिखाना चाहिए। साथ ही, बड़े भी स्वयं जिम्मेदारी से मोबाइल का उपयोग कर बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें।

मोबाइल न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही बुरा। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। यदि बच्चे मोबाइल को ज्ञान, रचनात्मकता और कौशल विकास का साधन बनाएँ, तो वही तकनीक उनके उज्ज्वल भविष्य का आधार बन सकती है। लेकिन यदि इसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग जारी रहा, तो यह उनके बचपन, शिक्षा और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

आज आवश्यकता मोबाइल छोड़ने की नहीं, बल्कि मोबाइल का सही, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग सीखने और सिखाने की है। यही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर (भारत)

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)

112	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (पुलिस, फायर, और एंबुलेंस)	104	स्वास्थ्य हेल्पलाइन (Health Helpline/Medical Advice)
		1915	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
100	पुलिस (Police)	1930	साइबर अपराध (Cyber Crime)
		139	रेलवे पूछताछ / सुरक्षा (Railway Enquiry / Security)
101	फायर ब्रिगेड (Fire Brigade)	1363	पर्यटन हेल्पलाइन (Tourist Helpline)
102/108	एम्बुलेंस सेवा (Ambulance)	1033	सड़क दुर्घटना या राष्ट्रीय राजमार्ग आपातकाल (Road Accident / National Highway Emergency)
1091	महिला हेल्पलाइन (Women Helpline)	14567	बुजुर्ग हेल्पलाइन (Elder Line)
		1551	किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center)
1098	चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline)	1906	गैस सिलेंडर (LPG) रिसाव या आपातकाल (LPG Gas Leak / Emergency)

2. राज्य / बिजली बोर्ड हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)

राज्य	हेल्पलाइन नंबर (टोल-फ्री)	वैकल्पिक संपर्क नंबर / वैबसाइट
हिमाचल प्रदेश (HPSEBL)	1912	1800-180-8060 | www.hpseb.in
उत्तर प्रदेश (UPPCL / अन्य)	1912	1800-180-8752 | www.uppcl.org
दिल्ली (BSES/TPDDL)	1912	वेबसाइट के माध्यम से चैटबॉट सपोर्ट www.bsesdelhi.com / www.tatapower-ddl.com
पंजाब (PSPCL)	1912	1800-180-1512 | www.pspcl.in
हरियाणा (DHBVN/UHBVN)	1912	1800-180-1833 | www.dhbvn.org.in / www.uhbvn.com
मध्य प्रदेश (MPPKVVCL)	1912	1800-233-1266, WhatsApp: 9425807257 www.mpez.co.in
उत्तराखंड (UPCL)	1912	1800-419-0405 | www.upcl.org

3. राज्यवार जल हेल्पलाइन नंबर

राज्य / विभाग	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / वेबसाइट
केंद्रीय / राष्ट्रीय	1800-121-2164	जल जीवन मिशन का टोल-फ्री नंबर | www.jaljeevanmission.gov.in
हिमाचल प्रदेश (स्थानीय)	1800-180-8009, 1100	जल शक्ति विभाग (SNK), शिकायत निवारण केंद्र
दिल्ली	1916	दिल्ली जल बोर्ड (24x7) | www.delhijalboard.nic.in
उत्तर प्रदेश	1076	सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) | www.up.gov.in
बिहार	1800-123-1121	पीएचईडी (PHED) पेयजल शिकायत | www.prdbihar.gov.in
राजस्थान	1800-180-6088	जलदाय विभाग (PHED) | www.jalday.rajasthan.gov.in
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सभी राज्य)	181 या 1902	सभी राज्यों की शिकायत और जानकारी के लिए

4. राज्यवार परिवहन (बस) हेल्पलाइन नंबर

राज्य / निगम	हेल्पलाइन नंबर	विवरण / उपयोग
हिमाचल प्रदेश (HRTC)	1100, 1800 180 8185	24/7 हेल्पलाइन, पूछताछ और शिकायत निवारण
दिल्ली (DTC)	011-22968836	आईएसबीटी (ISBT) पूछताछ
उत्तर प्रदेश (UPSRTC)	149, 1800 1800 151	24/7 टोल-फ्री सुविधा
राजस्थान (RSRTC)	181	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता
चंडीगढ़ (CTU)	1800 274 7400	टोल फ्री नंबर

इन हेल्पलाइन नंबरों को सेव करें और जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मनरेगा कर्मचारियों की जायज मांगों का सहानुभूतिपूर्वक होगा समाधान: कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद

जीत समाचार ब्यूरो

खन्ना/लुधियाना। पंजाब के कैबिनेट मंत्री एवं खन्ना के विधायक तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मचारियों की जायज मांगों का सहानुभूतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से समाधान करेगी। उन्होंने यह भरोसा घायल मनरेगा कर्मचारी और पुलिस अधिकारी का हालचाल जानने के दौरान दिया।

कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ खन्ना सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए मनरेगा कर्मचारी सौदागर सिंह और डीएसपी विनोद कुमार का हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनिंदर सिंह भसीन को दोनों घायलों का नि:शुल्क और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 20 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों के साथ लगातार बैठकें और संवाद जारी हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के स्थान पर नई योजना लागू करने का निर्णय है। वर्षों से इस योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों को नए सिस्टम में उचित अवसर मिलना चाहिए और सरकार उनकी इस मांग को गंभीरता से सुन रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए, जिसके चलते पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि, सरकार और मनरेगा कर्मचारियों के बीच कोई टकराव नहीं है तथा पंजाब सरकार सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और आपसी सहमति से करना चाहती है।

तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि मनरेगा कर्मचारियों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनकी जायज मांगों का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को कर्मचारियों की उचित मांगों पर लिखित आश्वासन देने के भी निर्देश दिए हैं।

वहीं, मनरेगा कर्मचारी यूनियन पंजाब के संरक्षक वरिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से मनरेगा योजना के तहत सेवाएं दे रहे हैं और उनकी मुख्य मांग रोजगार की सुरक्षा है। उन्होंने खन्ना में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यूनियन को कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर पूरा विश्वास है और यूनियन सरकार के भरोसे से संतुष्ट है।

इस अवसर पर एसएसपी खन्ना डॉ. दर्पण आहलूवालिया, एसडीएम स्वाति टिवाना, एसएमओ डॉ. मनिंदर सिंह भसीन, सिविल एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा मनरेगा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

19 जुलाई को लुधियाना के सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष एसआईआर-2026 कैंप - डिप्टी कमिश्नर

जीत समाचार लुधियाना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 अभियान को सफल बनाने के लिए 19 जुलाई (रविवार) को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु जैन ने दी।

उन्होंने बताया कि सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने, विवरण का सत्यापन कराने, आवश्यक दस्तावेज जमा करने तथा फॉर्म के डिजिटलीकरण में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित समय पर अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं और गणना प्रपत्र जमा करें, ताकि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण समय पर पूरा किया जा सके।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, बूथ लेवल एजेंटों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से भी अभियान में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को विशेष कैंप में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

जीत सच्ची खबर की
जीत समाचार
www.zeetsamachar.com

22 जुलाई को लुधियाना में होगी एनआरआई मीट, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू

जीत समाचार लुधियाना। पंजाब सरकार का एनआरआई मामलों का विभाग 22 जुलाई को लुधियाना में एनआरआई मीट आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे पंजाबियों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। यह जानकारी विभाग की विशेष सचिव अमनदीप कौर ने दी।

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 22 जुलाई को सुबह 11 बजे सोहन लाल पाहवा अहडिटोरियम, गुरु नानक भवन, फिरोजपुर रोड, लुधियाना में आयोजित होगा। इसमें लुधियाना, संगरूर, मलेरकोटला और बरनाला जिलों के एनआरआई भाग ले सकेंगे।

कार्यक्रम में एनआरआई मामलों के विभाग, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे प्रतिभागियों की शिकायतें सुनकर उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अमनदीप कौर ने कहा कि पंजाब सरकार एनआरआई समुदाय की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एनआरआई मीट का उद्देश्य विदेशों में रह रहे पंजाबियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकें।

उन्होंने संबंधित जिलों के सभी पात्र एनआरआई से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। इच्छुक प्रतिभागियों से अहनलाइन पंजीकरण कराने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि पंजीकरण के दौरान अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी तथा यदि कोई शिकायत पहले से दर्ज है तो उसकी जानकारी भी उपलब्ध कराएं, ताकि कार्यक्रम के दौरान मामलों का प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण किया जा सके।

जंडियाला गुरु में लोगों की समस्याएं सुनीं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील

जीत समाचार ब्यूरो

अमृतसर। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने शुक्रवार को जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र के रख मानावाला, सुरजन सिंह वाला और नांगल गुरु गांवों में आयोजित जनसभाओं के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनकल्याण, पारदर्शी प्रशासन और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के लोगों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनी कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस अवसर पर उन्होंने 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि अवैध नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाई जा रही है।

मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए सरकार का सहयोग करें और नशा तस्करों की सूचना प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि जनसहयोग से ही युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है और पंजाब को नशामुक्त बनाया जा सकता है।

उन्होंने ग्रामीणों से पंजाब सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपने गांवों के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया।

आईएचएम गुरदासपुर में बीएससी होटल मैनेजमेंट प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 27 जुलाई तक करें अप्लाई

जीत समाचार गुरदासपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम), गुरदासपुर ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय बी. एससी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 27 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

संस्थान के प्राचार्य (प्रभारी) अश्विनी काचरू ने बताया कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन संचालित आईएचएम गुरदासपुर को लगातार देश के शीर्ष होटल मैनेजमेंट संस्थानों में स्थान मिलता रहा है। लगभग 14 एकड़ में फैले परिसर में आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब, समृद्ध पुस्तकालय, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग छात्रावास, जिम, खेल स्टेडियम और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि नेशनल काउंसिल फहर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा द्वारा संचालित यह तीन वर्षीय बी.एससी. पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नई दिल्ली के शैक्षणिक सहयोग से संचालित किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रोडक्शन में डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध है।

प्राचार्य ने बताया कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 102 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आईएचएम, कैटरिंग टेक्नोलहजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बरियार (गुरदासपुर) के एडमिशन सेल से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 01874–222501, 87278–00636 या 98888–25351 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने वाले बीएलओ को जिला चुनाव अधिकारी ने किया सम्मानित

जीत समाचार ब्यूरो

गुरदासपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त आदित्य उप्पल ने सम्मानित किया। इस अवसर पर तहसीलदार (चुनाव) मनजिंदर सिंह बाजवा भी उपस्थित रहे।

इस दौरान फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 203 के बीएलओ सुरजीत सिंह को घर-घर गणना अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा करने पर सम्मानित किया गया।

जिला चुनाव अधिकारी आदित्य उप्पल ने सम्मानित बीएलओ की सराहना करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में बीएलओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि समर्पण, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारी अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बनते हैं।

उन्होंने जिले के सभी बीएलओ से अपील की कि वे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ पूरा करें।

उपायुक्त ने मतदाताओं से भी आग्रह किया कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान बीएलओ का पूरा सहयोग करें तथा अपने विवरणों का सत्यापन एवं अद्यतन कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।

ग्रामीण स्वच्छता मॉडल में बिलासपुर ने रचा इतिहास, डोर-टू-डोर प्लास्टिक कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना

जीत समाचार बिलासपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बिलासपुर ने ग्रामीण स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए हिमाचल प्रदेश का पहला जिला बनने का गौरव हासिल किया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर से प्लास्टिक कचरे के डोर-टू-डोर संग्रहण की सुव्यवस्थित व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की गई है।

इस अभिनव पहल के तहत पिछले आठ महीनों में आठ टन से अधिक सूखा प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार ने सदर विकास खंड की नौणी ग्राम पंचायत स्थित प्लास्टिक कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन केंद्र से एक टन से अधिक प्रोसेस्ड प्लास्टिक कचरे की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर बरमाणा सीमेंट संयंत्र के लिए रवाना किया। वहां को-प्रोसेसिंग तकनीक के माध्यम से उच्च तापमान पर प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण किया जाएगा।

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 2 अक्तूबर, गांधी जयंती के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि यह पहल बिलासपुर को प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता का मॉडल जिला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुई है।

उन्होंने बताया कि जिले के बिलासपुर सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नयना देवी जी विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्राम पंचायतों से घर-घर एकत्र किए गए सूखे प्लास्टिक कचरे को इन केंद्रों पर लाकर उसकी छंटाई, संपीड़न (बेलिंग) और प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके बाद वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बरमाणा सीमेंट संयंत्र भेजा जाता है।

इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग और बरमाणा सीमेंट संयंत्र के बीच समझौता (एमओयू) किया गया है। वहीं, डोर-टू-डोर संग्रहण के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एजेंसी टारगेट ग्रीन जोन पंचायतों से प्लास्टिक कचरा एकत्र कर संग्रहण केंद्रों तक पहुंचा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि अब तक आठ टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा चुका है, जिसे चरणबद्ध तरीके से वैज्ञानिक निस्तारण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही इस अभियान का विस्तार कंदरौर, बरठीं, चांदपुर, जुखाला, भराड़ी, डंगार, नम्होल सहित अन्य प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों तक भी किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह पहल केवल प्लास्टिक कचरे के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिलासपुर का यह मॉडल भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रुपिंदर कौर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी यशपाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

भरेड़ी में 22 जुलाई को लगेगा 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम, 9 पंचायतों की समस्याओं का होगा समाधान

जीत समाचार भोरंज। उपमंडल भोरंज के भरेड़ी में 22 जुलाई को 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्थानीय विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एसडीएम शशिपाल शर्मा ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 'सरकार गांव के द्वार' प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

एसडीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान लोगों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और मांगों का यथासंभव मौके पर ही निपटारा किया जाए। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया जाए तथा यदि किसी योजना से संबंधित औपचारिकताएं शेष हों तो उन्हें भी वहीं पूरा कराया जाए।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भी मौके पर ही जारी किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

शशिपाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनियां और सूचना स्टॉल भी लगाएं, जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक पात्र नागरिक उनका लाभ उठा सकें।

बैठक में तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह, सीडीपीओ सुनील कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी बलदेव चंदेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

टांडा मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक सहायता पैरामेडिक्स का प्रथम प्रशिक्षण बैच सम्पन्न

जीत समाचार ब्यूरों

धर्मशाला । डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में 14 से 16 जुलाई तक राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन रक्षक सहायता पैरामेडिक्स के प्रथम बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन उत्तर भारत की अत्याधुनिक हाई-फिडेलिटी सिमुलेशन लैब में किया गया।

हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कोर्स डायरेक्टर डह. मोनिका पठानिया के मार्गदर्शन में विशेषज्ञ चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों की टीम ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा, सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य गंभीर आपातकालीन परिस्थितियों में अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों और स्वयंसेवकों को आधुनिक जीवन रक्षक कौशलों से प्रशिक्षित करना था।

प्रशिक्षण में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, लैब तकनीशियनों, रेडियोग्राफरों, अहपरेशन थिएटर तकनीशियनों तथा मानव सेवा से जुड़े स्वयंसेवकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान आधुनिक हाई-फिडेलिटी सिमुलेशन तकनीक और महक ड्रिल के माध्यम से वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास कराया गया। साथ ही उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग, टीम समन्वय और त्वरित निर्णय क्षमता को भी परखा गया, ताकि प्रतिभागी किसी भी संकट की स्थिति में आत्मविश्वास और दक्षता के साथ कार्य कर सकें।

कोर्स डायरेक्टर डॉ. मोनिका पठानिया ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित एवं सक्षम मानव संसाधन तैयार कर प्रदेश की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक पैरामेडिक को जीवन रक्षक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके और प्रदेश की आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

धर्मशाला में 154.51 ग्राम चिट्टा बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

जीत समाचार ब्यूरों

धर्मशाला। कांगड़ा पुलिस के एंटी-चिट्टा अभियान के तहत सीआईए कांगड़ा और थाना धर्मशाला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने धर्मशाला बस स्टैंड के समीप टैक्सी स्टैंड से 154.51 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अल्टो कार (एचपी–37एफ–6091) को भी कब्जे में ले लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप कुमार (38 वर्ष) निवासी वृंदावन, पालमपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।

इस संबंध में थाना धर्मशाला में एफआईआर संख्या 115/2026 के तहत धारा 21, 29, 61 एवं 85 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

कांगड़ा पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा जिले में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

बैजनाथ जल शक्ति विभाग को मिले नए अधिशाषी अभियंता, अभिषेक शर्मा ने संभाला कार्यभार

जीत समाचार ब्यूरों

बैजनाथ। जल शक्ति विभाग, बैजनाथ को नए अधिशाषी अभियंता मिल गए हैं। अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को अधिशाषी अभियंता के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया।

इससे पूर्व अभिषेक शर्मा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि विभाग की लंबित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा जल शक्ति विभाग से संबंधित शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा।

बैजनाथ-पपरोला क्षेत्र के लोगों ने नए अधिशाषी अभियंता का स्वागत करते हुए उनसे क्षेत्र की पेयजल योजनाओं में तेजी लाने और जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में सुनीं लोगों की समस्याएं, समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश

जीत समाचार ब्यूरों

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करना सरकार की कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम ने सरकार और आमजन के बीच संवाद को और अधिक मजबूत बनाया है, जिससे लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में तेजी आई है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराना है। जनसुनवाई के माध्यम से आम नागरिक सीधे अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रख पा रहे हैं, जिससे शासन व्यवस्था अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनी है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हर नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा तथा विकास कार्यों को गति देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

मुख्यमंत्री सहारा योजना के 281 लाभार्थियों को 25.29 लाख रुपये की सहायता राशि जारी

जीत समाचार ब्यूरों

बिलासपुर।उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 की अप्रैल से जून तिमाही के लिए जिले के 281 पात्र लाभार्थियों को 25.29 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेज दी गई है।

उन्होंने बताया कि अब मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित तथा बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपचार और दैनिक जीवन-यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कैंसर, किडनी फेल्योर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, पार्किन्सन रोग तथा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।

राहुल कुमार ने कहा कि योजना से वंचित पात्र व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अहनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक लोकमित्र केंद्रों के जरिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज : योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे- हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम परिवार रजिस्टर की प्रति, राशन कार्ड, बैंक या डाकघर बचत खाते का विवरण, आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र), मेडिकल प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा रिकॉर्ड, चार लाख रुपये तक का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

उपायुक्त ने कहा कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पात्र व्यक्ति तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

डिजाइन डॉक्यूमेंट पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, 15 प्रशिक्षुओं ने लिया भाग

जीत समाचार सुंदरनगर। जाईका परियोजना हमीरपुर के सौजन्य से कृषक प्रशिक्षण केंद्र, सुंदरनगर में 'डिजाइन डॉक्यूमेंट' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कृषि विभाग के 15 प्रशिक्षुओं, जिनमें कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ प्रारूपकार और सर्वेक्षक शामिल थे, ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ उप-प्रधानाचार्य डॉ. जगदीश कुमार जंजीहा ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजाइन दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और यह परियोजना की सफलता की आधारशिला हैं।

प्रशिक्षण के दौरान संसाधन व्यक्ति डॉ. पी.एल. शर्मा ने डिजाइन डॉक्यूमेंट की अवधारणा, महत्व, आवश्यकता, लाभ तथा त्रुटिपूर्ण प्रारूप से जुड़े संभावित जोखिमों की विस्तृत जानकारी दी।

वहीं, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता आर.के. कौंडल ने सिंचाई संरचनाओं के डिजाइन, टैंक क्षमता की गणना तथा उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए डिजाइन दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया।

अधिशाषी अभियंता ललिता कुमारी ने दस्तावेजों के ऑडिट और उनमें निरंतर सुधार की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा अभियंता मंजीत कुमार ने डिजाइन दस्तावेजों के जीवन चक्र, योजना निर्माण, आलेखन, समीक्षा, संपादन और अंतिम रूप देने की विभिन्न प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधानों पर भी विस्तृत चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाना तथा परियोजनाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डिजाइन दस्तावेज तैयार करने की क्षमता विकसित करना रहा।